भारत सरकार

भारी उद्योग मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 421

02.12.2025 को उत्तर के लिए नियत

पीएम ई-ड्राइव योजना

421. **श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरेः**

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) प्रधानमंत्री ई-ड्राइव योजना के अन्तर्गत आज तक वितरित सब्सिडी का ब्यौरा क्या है;

(ख) ई-एम्बुलेंस को सब्सिडी प्रदान करने हेतु दिशा-निर्देश तैयार करने की स्थिति क्या है तथा उक्त योजना के अंतर्गत ई-एम्बुलेंस को सब्सिडी प्रदान करने हेतु विशेष रूप से कितना बजट आवंटित किया गया है;

(ग) विभिन्न शहरों में विशेष रूप से चार्जिंग अवसंरचना की स्थापना के लिए वितरित सब्सिडी का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने ईवी चार्जिंग अवसंरचना के लिए सब्सिडी प्राप्त करने में रुचि दिखाई है जैसा कि योजना के अंतर्गत परिकल्पित है;

(ङ) पीएम ई-ड्राइव योजना किस प्रकार मुम्बई और दिल्ली जैसे प्रमुख शहरों में बसों की कमी को दूर करेगी;

(च) इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने वाले महाराष्ट्र के अन्य शहरों का ब्यौरा क्या है; और

(छ) क्या यह सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठाए जा रहे हैं कि इस योजना के अंतर्गत बनाया गया चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक से इस्तेमाल हो और आसानी से मिल सके?

उत्तर

भारी उद्योग राज्य मंत्री

(श्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा)

(क) : पीएम ई-ड्राइव स्कीम के तहत 23/11/2025 तक 1,634.62 करोड़ रुपये की सब्सिडी संवितरित की गई है।

(ख) : पीएम ई-ड्राइव स्कीम के अंतर्गत ई-एम्बुलेंस के लिए 500 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। ई-एम्बुलेंस के लिए दिशानिर्देश अधिसूचित करने हेतु हितधारकों के साथ परामर्श किया गया है। अन्य खंडों सहित ई-एम्बुलेंस के लिए स्कीम को 31.03.2028 तक

बढ़ा दिया गया है, लेकिन ई-दुपहिया और ई-तिपहिया के लिए अंतिम तिथि 31.03.2026 ही रहेगी।

(ग) और (घ) : पीएम ई-ड्राइव स्कीम के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सार्वजनिक चार्जिंग अवसंरचना (ईवीपीसीआई) की स्थापना के लिए 2,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। 23/11/2025 तक ईवीपीसीआई की स्थापना के लिए कोई अनुदान संवितरित नहीं किया गया है। दो तेल विपणन कंपनियों ने पीएम ई-ड्राइव स्कीम के तहत ईवीपीसीआई की स्थापना के लिए रुचि दिखाई है और प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं।

(ङ) और (च) : पीएम ई-ड्राइव स्कीम के तहत, मुंबई को 1,500 ई-बसें और दिल्ली को 2,800 ई-बसें आवंटित की गई हैं। महाराष्ट्र में मुंबई के अलावा पुणे को भी 1,000 ई-बसें आवंटित की गई हैं।

(झ) : उपयोग और पहुंच सुनिश्चित करने के लिए, पीएम ई-ड्राइव स्कीम के तहत ईवी चार्जिंग बुनियादी ढांचे के लिए दिशानिर्देशों को अधिसूचित किया गया है और राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझा किया गया है।

****